प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

25.10.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19.45बजे

मुख्य समाचार

- राज्य सरकार ने आपदा राहत पैकेज को पूरे प्रदेश में लागू करने का लिया निर्णय–पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान की एवज में दिए जाएंगे सात लाख रूपए।
- प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन को दी मंजूरी– नगर निगमों के महापौर व उपमहामौर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया।
- स्वास्थ्य विभाग में 4 सौ स्टाफ नर्सों की होगी नियुक्ति– राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना शुरू करेगी सरकार।

और

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार।

अब समाचार विस्तार से..........

मंत्रिमंडल

प्रदेश मंत्रिमंडल ने पूरे प्रदेश में आपदा राहत पैकेज लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। अभी तक ये राहत राशि मंडी जिले के लिए लागू थी लेकिन अब पूरे प्रदेश में उन लोगों को राहत दी जाएगी जिनके मकान आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों में जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह नष्ट हुए हैं उन्हें चार लाख रूपए की पहली किश्त दी जाएगी जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए डेढ़ लाख रूपए एकमुश्त दिए जाएंगे।

बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रकिया शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। इस संबंध में पंचायती राज विभाग को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने नगर निगमों के महापौर और उपमहापौर के कार्यकाल को अढ़ाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में चार सौ स्टाफ नर्सों के पद सृजित करने को मंजूरी दी और ये नियुक्तियां राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इसके अलावा जे.ओ.ए. आईटी के 3 सौ पदों को जॉब ट्रेनी के रूप में सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में एसएमसी शिक्षकों, आईटी कम्प्यूटर अध्यापकों, मिड–डे–मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में भी इस वर्ष पहली अप्रैल से 5 सौ रूपये प्रति माह की बढ़ौतरी करने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ब्याज अनुदान सहित भूस्थलीय और ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने को लेकर योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का नाम अब राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा। इसके तहत जनजातीय व गैर–जनजातीय क्षेत्रों में सौ किलोवॉट से दो मेगावॉट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पुरूष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की अनुमति भी दी।

चंद्र कुमार

पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि कांगड़ा जिले के ढगवार में मिल्क प्लांट प्रदेश का सबसे उन्नत दुग्ध संयंत्र होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य करेगा। चंद्र कुमार ने संयंत्र के कार्यों के प्रगति का निरीक्षण किय और अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दुग्ध संयंत्र की क्षमता डेढ़ लाख लीटर प्रति दिन की होगी और इस पर लगभग 2 सौ 25 करोड़ रूपए की लागत आएगी। पशुपालन मंत्री ने बताया कि अभी तक लगभग 41 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई एतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गाय का दूध 50 रूपए और भैंस का दूध 61 रूपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अलावा पशुपालकों से गोबर की खाद 3 सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यू–ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा।

विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश के एक सौ स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने के ऐतिहासिक फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने आज चंबा जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ढाडू के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्यतिथि के रूप में शिरकत की। पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैथली से बिलासपुर और जल्दा से जोत संपर्क मार्ग के निर्माण को लेकर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को दी जा रही राहत राशि का हिसाब राज्य सरकार को लोगों को देना चाहिए। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले अढ़ाई वर्षों में आपदा के लिए केन्द्र द्वारा दी गई 5 हज़ार 5 सौ करोड़ रूपये की धन राशि का 10वां हिस्सा भी राज्य सरकार आपदा प्रभावितों पर खर्च नहीं कर पाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 15 सौ करोड़ रूपये का विशेष आर्थिक पैकेज हिमाचल को हर हाल में मिलेगा और राज्य सरकार को इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में हजारों घर नष्ट हो गए हैं और लोगों को राहत पहुंचाने के बजाए मुख्यमंत्री व उनके मंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य पथ परिवहन निगम में अनियमितताओं के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। जयराम ठाकुर ने नगर निगम शिमला के महापौर व उपमहापौर के कार्यकाल को अढ़ाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने पर कहा है कि सरकार चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपनी नाकामी और जनता के मूड़ का पता चल गया है।

सेब मंडी

सोलन की सेब मंडी में दो आढ़तियों पर बागवानों ने 25 लाख रूपए की अदायगी न कर फरार होने का आरोप लगाया है। ए.पी.एम.सी के सचिव राघव सूद ने बताया कि इस बारे में उनके पास बागवानों की शिकायतें आई हैं और आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- राज्य सरकार ने आपदा राहत पैकेज को पूरे प्रदेश में लागू करने का लिया निर्णय–पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान की एवज में दिए जाएंगे सात लाख रूपए।
- प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन को दी मंजूरी– नगर निगमों के महापौर व उपमहामौर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया।
- स्वास्थ्य विभाग में 4 सौ स्टाफ नर्सों की होगी नियुक्ति– राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना शुरू करेगी सरकार।

  और
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार।